**डाक विभाग द्वारा योजनाओं को लागू न किया जाना**

1710. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जुलाई, 1996 के "नवभारत टाइम्स" में "डाक-तार विभाग की योजनाएं चार महीने ठप्प" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा):** (क) और (ख) जी हां। 14 जुलाई, 1996 के नवभारत टाइम्स में संबंधित न्यूज आइटम डाक विभाग के कार्य पर एक अनुमानित टिप्पणी है, जिसके समर्थन में तथ्य नहीं दिए गए हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाए गए संबंधित वार्षिक प्लानों के अनुसार विभाग के विकास कार्यक्रम विधिवत् रूप से कार्यान्वित किए गए हैं। चालू वर्ष 1996-97 के दौरान, योजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन वित्त वर्ष के प्रथम चार महीनों के लिए लेखानुदान के माध्यम से आरम्भ में सुलभ कराए गए संसाधनों के अनुरूप है। डाक काउंटरों के कम्प्यूटरीकरण का कार्यक्रम गत तीन वर्षों के दौरान अच्छा चल रहा है हालांकि योजना अवधि के आरंभिक दो वर्षों के दौरान प्रारंभिक कठिनाइयों के कारण इसकी गति धीमी रही। फंड की कमी के कारण विभाग ने कोई भी विकासात्मक कार्यक्रम रोका या स्थगित नहीं किया गया। अधिकांश डाक सेवाओं द्वारा अर्जित राजस्व प्रचालन लागत की पूर्ति करने में अपर्याप्त है। इसलिए विभाग को उपयुक्त फंड के लिए आवश्यक बजटीय सहायता प्रदान की गई है।

जहां तक वर्ष 1996-97 में नए डाकघर खोलने का संबंध है विभाग का 80 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 150 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य है और संबंधित सर्किलों को इनका आवंटन कर दिया गया है। डाकघर मानदंडों की पूर्ति होने और संसाधनों की उपलब्धता पर ही खोले जाएंगे। अब तक चालू वर्ष के दौरान 20 विभागीय शाखा डाकघर तथा दो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर मंजूर किए जा चुके हैं। पंचायत संचार सेवा केन्द्रों के संबंध में चालू वर्ष के लिए 250 का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को भी सर्किलों को आवंटित कर दिया गया है, इसमें जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 60 केन्द्र शामिल हैं। नए डाकघर खोलने के संबंध में विभाग के योजना लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्यवाही चल रही है।

विभाग सरकार के मितव्ययिता संबंधी अनुदेशों का भी अनुपालन कर रहा है। डाक दरों के संशोधन से संबंधित प्रक्रिया सरकार की वार्षिक बजट प्रक्रिया का नियमित अंग है।

**Statutory Development Board for Konkaa region of Maharashtra**

1711. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the decision taken by Government on the proposal for setting up a Statutory Development Board for Konkan Region of Maharashtra; and

(b) by when the requisite legislation for amendment of the Consitution is likely to be brought before Parliament?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD: MAQBOOL DAR): (a) and (b) The matter is under consideration. Keeping in view the legal and constitution complexities involved in the issue, it would not be possible to lay down a definite time frame to finalise it.

**अमरीका द्वारा भारतीय ऊनी वस्त्रों पर रोक लगाया जाना**

1712. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका और कुछ यूरोपीय देशों ने भारत में निर्मित ऊनी परिधानों के आयात पर एकतरफा रोक लगाने की घोषणा की है;

(ख) विश्व व्यापार संगठन इस संबंध में दोनों देशों के बीच एक बैठक आयोजित करने का विचार रखता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) विश्व व्यापार संगठन द्वारा दोनों देशों के बीच ऐसी बैठक का आयोजन कब तक किये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) से (ङ) भारतीय अमरीकी वस्त्र करार तथा ऊरूग्वे दौर के वस्त्रों एवं क्लोथिंग पर करार (ए टी सी) के प्रावधानों के अंतर्गत, अमरीका सरकार ने श्रेणियों 434 (जैंट्स कोट), 435 (लैडीज कोट) तथा 440 (बुनी हुई शर्ट्स तथा ब्लाऊज) में भारत से ऊनी परिधानों के आयात पर एकपक्षीय प्रतिबंध (कोटा) लगाए थे।

ए० टी० सी० के प्रावधानों के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के वस्त्र प्रबोधन निकाय (टीएमबी) ने अमरीका की कार्यवाही की समीक्षा की। अमरीका द्वारा 434 तथा 435 श्रेणियों पर लगाए गए प्रतिबंध अब हटा लिए गए हैं। श्रेणी 440 के संबंध में सरकार ने डब्ल्यू टी ओ के विवाद समाधान निकाय (डीएसबी) में मामला उठाया है तथा इस मामले में निर्णय देने के लिए डीएसबी ने एक पैनल बनाया है।

**ISPs Plan of Dumping Arms**

1713. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to the Intelligence Agencies, Pakistan's ISI is working on a calculated plan to dump weapons in the country for use at an appropriate time;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the measures taken by Government to thwart their designs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) to (c) Government is aware that Pakistan's ISI agents have been making concerted efforts to establish foot-hold at certain places in India for subversive and espionage activities. Pak ISI has even been using smugglers along the borders and through the coastal regions as conduits to push in arms, ammunition, explosives and heroin etc., in India.

The Government is taking all necessary steps to combat and frustrate the designs of ISI by sensitising and gearing up the intelligence machinery, sharing of intelligence, and by coordinated action by concerned Central and State agencies. The Police and Intelligence organisations are under instructions to neutralise Pak ISI modules and activities in all parts of the country whenever and wherever these come to notice.

**Opening of Post Office at Kota Giwai in Aimora District**

1714. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a), whether Government have received some requests from the people of Kota Giwai village in Aimora district of Uttiir Pradesh;

(b) whether it is a fact that there is no post office within a distance of 4 km. from Kota Giwai;

(c) if so, whether Government would give priority for opening of post office at Kota Giwai; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) to (c) Yes, Sir.

(d) The proposal for opening of an extra Deparmental Branch Post Office at Kota Giwai in Aimora -District of Uttar Pradesh was considered under Annual Plan, 1994-95. It could not however, be opened due to resource constraints. As soon as resources are available, it will be opened.

**एक्सप्रैस हाइवेज का निर्माण**

1715. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995 तक देश में कितने एक्सप्रैस हाइवेज के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है;

(ख) एक्सप्रैस हाइवेज निर्माण के लिए स्वीकृत प्रावधान क्या है;

(ग) इन हाइवेज के निर्माण के लिए प्रति कि०मी० अनुमानित लागत कितनी है; और